







# क्या सरदार >> विचार

“ धनखड़ का  
कहना था कि  
न्यायालय यह  
नहीं कर सकता, यह  
काम राज्यपाल और  
राष्ट्रपति का है। लेकिन  
सवाल यह है कि  
राज्यपाल जिसका काम  
संविधान सम्मत व्यवहार  
करना है अगर वह केंद्र  
सरकार के अधीन काम  
करके राज्य की विधायी  
व्यवस्था को बाधित  
करने का प्रयास करे तो  
क्या किया जाए? क्या  
किया जाए अगर देश  
के संघीय ढांचे को चोट  
पहुंचाई जा रही हो? क्या  
किया जाए अगर एक  
चुनी हुई विधायिका, जो  
नागरिकों के लिए  
कानून बनाने के लिए  
संवैधानिक स्व से  
बाध्य है।

# संपादकीय

## झूठे दावे और कोचिंग इंडस्ट्री का कड़वा सच

सही है कि हाल के दशकों में ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में कोचिंग संस्थानों की भूमिका बढ़ती गई है। बल्कि आज स्थिति यह हो गई है कि शिक्षा जगत के दायरे में इसे कोचिंग उद्योग के नाम से जाना जाने लगा है। मगर इस क्रम में बनी निर्भरता के समांतर बहुत सारे कोचिंग संस्थान अपने यहां दाखिले के लिए जिस तरह के दावे करते हैं, अपनी उपलब्धियों, सुविधाओं और संसाधनों को इस कदर बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं कि कई विद्यार्थी इसके प्रभाव में वहां चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अन्य संस्थान में पढ़ाई किए सफल अभ्यर्थी को वे अपने यहां का बता दें। हालांकि कई बार ऐसे दावे झूठे निकलते हैं। कोचिंग संस्थानों की इस प्रवृत्ति पर कई बार सवाल उठ चुके हैं, सरकार ने सख्ती बरतने की बात कही है, खुद सबौच्च न्यायालय भी कह चुका है कि कई कोचिंग संस्थान अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलावड़ कर रहे हैं। मगर अलग-अलग तरीके अपना कर झूठे दावे करने के चलन पर अब तक रोक नहीं लगाई जा सकी है। अब एक बार फिर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने कोचिंग संस्थानों की ओर से परोसे जाने वाले भ्रम पर शिकंजा कसने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है। उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित इस निकाय ने उनके लिए पिछले वर्ष निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत कोचिंग संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके विज्ञापन 'स्टीक, स्पष्ट हों और भ्रामक दावों से मुक्त' हों; विद्यार्थियों के दाखिले को लेकर बताई जाने वाली जानकारी में पूरी पारदर्शिता हो। यह छिपा नहीं है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के मद्देनजर कोचिंग संस्थान जिस तरह की प्रचार सामग्री जारी करते हैं, उनका केंद्रीय भाव यही होता है कि उनके यहां पढ़ाई करने के बाद सफलता की गारंटी और चयन की संभावना 'सौ फीसद' होगी। हकीकत यह है कि कोचिंग संस्थानों और उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और उसके मुकाबले नौकरी के लिए सीटें सीमित या बहुत कम संख्या में होती हैं। ऐसे में सबको 'सौ फीसद चयन' की गारंटी देना भ्रम परोसने से कम नहीं है। गौरतलब है कि आइआइटी-जेर्झर्इ परीक्षा के नतीजों आमतौर पर इसी तरह की किसी बड़े महत्व की परीक्षा के नतीजों

के बाद कई कोचिंग संस्थानों की ओर से ऐसे दावे किए जाते हैं कि उनके यहां पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने कामयाबी हासिल की है। इस क्रम में वे कई बार दूसरे संस्थानों के विद्यार्थी का नाम भी फर्जी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद यही होता है कि इस तरह के प्रचार को देख कर नए विद्यार्थी उनके संस्थान में दाखिला लेने को लेकर प्रभावित होंगे और इस तरह उनके कारोबार का विस्तार होगा। जबकि इसके बरक्स हकीकत यह होती है कि बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों का ऐसा दावा करने वाले संस्थानों से कोई वास्ता नहीं होता। कोचिंग संस्थानों को यह स्पष्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि सीमित अवसरों के दौर में सभी अभ्यर्थियों की शत-प्रतिशत सफलता की गारंटी वे किस आधार पर देते हैं। इस तरह के दावे एक तरह से झूठ का कारोबार होते हैं, जिसके जाल में फंस कर बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना आमतौर पर अधूरा रह जाता है। ऐसे में अपने संसाधनों और क्षमताओं के बारे में बढ़-चढ़ कर झूटे दावे करने वाले कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाना वक्त की जरूरत है।

यह में यह कानून 'समानता का अधिकार', 'धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार' और संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह सभी अधिकार संवैधानिक गारंटी प्राप्त मूल अधिकारों के श्रेणी में आते हैं। अब जब अपने इन अधिकारों के सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय सीधे सरकार न्यायालय जाने के अनन्त अधिकार (अनुच्छेद 32) का इस्तेमाल कर रहा है तो सरकार असहज हो रही है। अल्पसंख्यकों का पक्ष सुनने और कानून के प्रथम दृष्टान्त देखने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली पीठने इस कानून के अनुपालन पर फ़लिहाल अगली मुनवाई तक रोक लगा दी है। अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई यह राहत केंद्र सरकार और समूच्च भारतीय जनता पार्टी को नापावार गुजरी है। देश वे कानून मंत्री का कहना है कि जिस तरह न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है वह ठीक नहीं है "अगर कल के दिन सरकार ने भी न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप किया तब क्या होगा।" मेरा सवाल है कि क्या भारत का कानून मंत्र भारत की सीधी अदालत को धमकी दे रहा है आखिर इस कानून में ऐसी क्या खामी है जिसके न्यायिक समीक्षा को लेकर केंद्र सरकार विचलित हो रही है? न्यायालय ने यहीं तो पूछा है कि सदियों पुराना 'वक़फ़ बाय यूज़र' के लिए पीड़ित पक्ष दस्तावेज़ कहाँ से जुटाएगा? अगर दस्तावेज़ नहीं जुटा सकता जिसकी पूरी संभावना है, तो वह जमीन सरकार अपने कब्जे में ले लेगी; न्यायालय ने समानता के अधिकार का हवाला देते हुए यहीं तो पूछा है कि जब मन्दिर व न्यासों में मुसलमान नहीं हो सकते तो वक़फ़ बोर्ड में हिंदुओं को किस आधार पर जगह दी गई है असल में सरकार यह चाहती है कि वो संविधान व जैसे चाहे वैसे तोड़े-मरोड़े और जिसे संविधान ने संविधान का अभिरक्षक बनाया है वह मूल दर्शक बनकर सरकार की हाँ में हाँ मिलाता रहे, अगर ऐसे नहीं किया तो न्यायपालिका को 'टारगेट' किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुर्घट का कहना है कि भारत में 'गुह्युद्ध' चल रहा है औ इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संजीव खन्ना, जिम्मेदार हैं। दुबे यह सब सिफ़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देश की सीधी अदालत ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर उनके साथ खड़े होकर सरकार से सवाल पूछ लिया। दुबे यह सिफ़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीधी न्यायालय ने केंद्र सरकार

को यह याद दिला दिया कि भारत के संविधान 'समानता का अधिकार' प्रदान किया गया है और इसे किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जा सकता है। अब तक अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने वाले राजनैतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं वाले निशाना बनाया जाता था और अब यह निशाना स्वतंत्र न्यायपालिका पर साधा जा रहा है। मुझे तो कहा गृहयुद्ध नहीं दिख रहा है। मेरी इतिहास की समझ मुझे गृहयुद्ध का सेंस तब देती है जब कुछ ऐसा हो जैसा कि चीनी गृहयुद्ध में हुआ, जो हालत तब बने जब अमेरिकी गृहयुद्ध हुआ या फिर रूसी गृहयुद्ध। इसके अलावा अगर इस सदी की बात करें तो जैसा कि मैं हुआ। सबाल यह है कि निशिकांत दुबे अब उनकी पार्टी क्या यह बताना चाहती है कि अन्यायपालिका ने अल्पसंख्यकों का साथ दिया गृहयुद्ध छिड़ा जाएगा? क्योंकि बीजेपी के पास एक 'विकृत इतिहास दर्शन' है इसलिए अगर मान भी दें कि गृहयुद्ध चल रहा है तो दुबे जी को यह बताना चाहिए कि गृहयुद्ध क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं? कैसे निपट रहे हैं? मुद्दा सिर्फ़ इतना है कि देश की सभी अदालत आज अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी कैसे हो गई? केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक अधिकारों के हनन की लत पड़ चुकी है, चाहे बात- तीव्र तलाक़ की हो, उअ-उठ-फल्प की हो या बीजेपी शासित राज्यों में लाए जा रहे तथाकथित समान नागरिक संहिता के कानूनों की। जब तक बिना न्यायिक हस्तक्षेप के अल्पसंख्यकों के घर गिराये जाते रहें तब उन्हें दूपर दर्जे का नागरिक समित किया जाता रहें और संसद में खड़े होकर उनको गालियाँ देने वाला कार्यक्रम चलता रहे तब तक सब ठीक है लेकिन अब उन्हें न्यायालय से समर्थन मिलने लगे तो गृहयुद्ध वधमकी शुरू! निशिकांत दुबे भूल रहे हैं कि यह संप्रदाय देश भारत है, जिसकी नीव में ऑबेडकर, गांधी और नेहरू जैसे लोग हैं, यह विल्सन फिस्क का हेले किचन नहीं जहाँ कानून और संविधान को किया सफेदपोश का गूलाम बनाकर रख दिया जाए (डेविल वेब सीरीज)। दुबे भारत के 543 लोकसभा सांसदों में से एक सांसद हैं वह स्वयं देश की संसद बनने की कोशिश न करें। जिस न्यायालय पर चाहे भर करने से पहले (आरोप तो बहुत दूर की बात है) लोकसभा का स्पीकर दस बार सोचता है तो से पहले अपने स्पीकर से पूछना चाहिए था। वह ए

सांसद हैं जिन्हे जनता ने चुनकर भजा है उन्हें ऐसे जलत्वों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। असल में निशिकांत दुबे को अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है यह सब कुछ उस पारिस्थितिकी का हिस्सा है जो देश में दशकों तक शासन करने की ज़दि पाल बैठी है। अब इसके लिए चाहे उसे जिस भी संस्थान को 'किनारे' लगाना पड़े वो लगाने को तैयार हैं। पिछले दस सालों में सर्वोच्च न्यायालय एकमात्र संस्था बची है जहाँ अभी भी यह पारिस्थितिकी पुरी तरह हावी नहीं हो सकी है। पर कोशिश जारी है। और यह कोशिश हर स्तर पर की जा रही है, निशिकांत तो उसमें सबसे निचले पायदान पर है। इन दिनों इस मौर्चे का नेतृत्व भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सम्भाल रखा है। उनका पद बेहद संवेदनशील है क्योंकि यह संवैधानिक है। लेकिन शायद धनखड़ एसा नहीं सोचते। चूँकि संविधान उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सीधी आलोचना का कोई अधिकार नहीं देता, फिर भी वो कर रहे हैं इसलिए नागरिक के तौर पर उपराष्ट्रपति की रचनात्मक आलोचना का अधिकार सभी को है, भले ही यह संविधान में सीधे सीधे ना वर्णित किया गया हो। उपराष्ट्रपति धनखड़ पद संभालने के बाद से लगातार सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना करते रहे हैं। हाल में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 'तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल' फैसले की आलोचना की। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल करके वर्षों से लंबित 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की 'अनुमति प्रदान की गई' मानकर पारित कर दिया। धनखड़ का कहना था कि न्यायालय यह नहीं कर सकता, यह काम राज्यपाल और राष्ट्रपति का है। लेकिन सवाल यह है कि राज्यपाल जिसका काम संविधान सम्मत व्यवहार करना है अगर वह केंद्र सरकार के अधीन काम करके राज्य की विधायी व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करे तो क्या किया जाए? क्या किया जाए अगर देश के संघीय दांचे को चोट पहुँचाई जा रही हो? क्या किया जाए अगर एक चुनी हुई विधायिका, जो नागरिकों के लिए कानून बनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, के कार्यों को रोक दिया जाए? क्या किया जाए अगर संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान काँही गला घोंटने लगें? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान सभा ने अनुच्छेद-142 का ग्रावधान किया। अनुच्छेद 142

# खाद्य और जल सुरक्षा को गंभीर चुनौती



विशेषकर जीवारम् ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से। जैसे-जैसे वैश्विक तपामान बढ़ता है, ग्लोशियर बनने की तुलना में कहीं अधिक तेजी से पिघलते हैं, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। यह संकट के बल बर्फ के खत्म होने का नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व पर मंडराते खतरे का संकेत है। सरकारी रिपोर्टों और वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, हिमालयी ग्लोशियर जलवायु परिवर्तन के कारण अलग-अलग दरों से तेज़ी से पिघल रहे हैं। यह न केवल पर्यावरणीय असंतुलन का संकेत है, बल्कि दक्षिण एशिया की लगभग 160 करोड़ आबादी के लिए जल संकट और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ा रहा है। करीब 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले ये ग्लोशियर ताजे पानी के विशाल धंडार हैं, जिन पर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की जलापूर्ति निर्भर करती है। इन्हें

तीसरा ध्रुव' कहा जाता है। बीते 40 वर्षों में 440 अरब टन बर्फ हिमालय से पिघल चुकी है, और केवल वर्ष 2010 में ही 20 अरब टन बर्फ का नुकसान हुआ। यह स्थिरता और भी चिंताजनक तब हो जाती है जब वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यदि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो सर्दी के अंत तक एक-तिहाई और यदि यह वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो दो-तिहाई हिमालयी ग्लेशियरों का समाप्त हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चेतावनी दी कि नेपाल के पहाड़ों से एक-तिहाई बर्फ पहले ही खट्ट हो चुकी है भारत और चीन जैसे प्रमुख कार्बन उत्सर्जकों के बीच बसे इस क्षेत्र में नेपाल के ग्लेशियर 65 फीसदी तक पिघल चुके हैं, और अगर यहीं हाल रहा तो हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र के 75 फीसदी ग्लेशियर इस सदी के अंत तक नष्ट हो सकते हैं। ग्लेशियरों के अंतर्गत हो सकते हैं—

बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन ग्लेशियरों के विनाश का प्रमुख कारण बन रहे हैं। यह केवल बर्फ के पिघलने का संकट नहीं, बल्कि एक विनाशकारी सुनामी की तरह है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, द्वीप और टटीय इलाके डूब रहे हैं, बाढ़ और सूखा बढ़ रहे हैं, और नदियां संकट में हैं। हमें अपनी जीवनशैली में बदलाव लाने के साथ-साथ हिमालय क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप पर अंकुश, जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण करना होगा, ताकि हम कुछ सकारात्मक बदलाव देख सकें। अन्यथा, वह दिन दूर नहीं जब पानी की कमी, सूखे और नदियों का खात्मा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। ग्लेशियरों को बचाना सिर्फ बर्फ को बचाना नहीं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ीयों और जीवन के अस्तित्व को बचाना है।

## आर्ट एंड कल्पर : कृमुदिनी ने नृत्य में लोक का आलोक संजोया

- डॉ. राजेश कुमार व्यास  
कुमुदिनी लाखिया नृत्य और नृत के अन्तः संबोधों की संवाहक थीं। उनका अवसान भारतीय कला के एक युग का बेछोह है। कुमुदिनी ने कथक में पहले दीती आ रही परम्पराओं को पुनर्नवा कर उसे आधुनिक दृष्टि दी। वह विरल नर्तकी थीं। नृत्य में निहित भावनाओं और आंगिक हाव-भाव संग वह नृत्य-नृत करती थीं। माने सुदृश शारीरिक गति औ लल्य में वह देह के गान की रसानुभूति कराती थावों का अनुठा संसार रचती थीं। कथक में अमूर्तन की दृष्टि पहले-पहल केसी ने दी तो वह कुमुदिनी लाखिया कुमुदिनी ने कथक को मंचीय-विस्तार देया। मंच पर खाली जगहों, वहाँ की नेत्रिक्याता में नृत्य और नृत की ऊँची उन्होंने उमंग भरी। कथक में समूह नृत्य की प्रवर्तक वही थीं। नृत्य-नृत के भैरव समझाते कुमुदिनी ने कथक के बंधे-बंधाए नियमों के अनुशासन को बरकरार खत्ते हुए भी कथक को समयानुरूप आधुनिक दृष्टि दी। सर्वथा नया व्याकरण विकसित किया। बंधे-बंधाए कथानक-

सका। पर इस दौरान उनकी कला की मौलिकता को निरंतर जिया। वह नाचती तो आंगिक क्रिएएं, विचार बन हमसे संवाद करती। नृत्य में देह का विसर्जन कर विचार का प्रगटीकरण किसी ने किया तो वह कुमुदिनी लाखियां थीं। उनकी नृत्य-प्रस्तुतियां 'सेतु', 'चक्षु', 'दुविधा', 'कोट' देखते सदा ही यह लगता है कि नृत्य में अमृत भी खंड-खंड अखंड विचार बन हममें समाता चला जाता है। कुमुदिनी ने नृत्य में लोक का आलोक संजोया। छाया-प्रकाश, रंगों और परिधानों के बंधे-बंधाए ढर्टे को तोड़ते कथक में कोरियोग्राफी का नया शास्त्र आरंभ किया। कथक में बेले सरीखी छलांग लगाते उड़ान के दृश्य प्रस्तुत करना, तैरना, फिसलना और उत्तरने की जो अंग-क्रिएएं कुमुदिनी ने इजाज कीं, वह कथक के भविष्य का उजास है। नृत्य में अपने आपको वह विसर्जित कर देती थीं। यह उनकी कला-दृष्टि ही थी, जिसमें उन्होंने नृत्य में बाधा बनते दुपट्टे को हटाकर पोशाक की रुढ़ियों को तोड़ा।









# उर्वशी रौतेला

के खिलाफ कार्यवाई हो... ' मंदिर  
वाले बयान पर बुरी फँसी एकट्रेस

फिल्म एकट्रेस उर्वशी रौतेला अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। कई बार सोशल मीडिया पर उन्हें अपने बयानों की वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। एक बार फिर से वो विवादों में घिर गई हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया, जिसको लेकर अब उनके खिलाफ कार्यवाईओं की मांग हो रही है। उनका कहना है कि उत्तराखण्ड में ब्रदीनाथ में उनका मंदिर है।

उनके इस बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। साधु संतों के साथ-साथ लोगों में भी

उनके खिलाफ

नाराजगी दिख रही है।

ब्रदीनाथ मंदिर के पूर्व धर्म

अधिकारी भुवन उनियाल ने

कहा, हम इसका धोर विरोध

करते हैं। ये बात गलत है।

समाज में इसका गलत

सदेश जाएगा। हमतो

कहते हैं कि सरकार

को ऐसे लोगों के

खिलाफ एक्शन लेना

चाहिए। जब से सुना

है कि उर्वशी रौतेला

ब्रदीनाथ की भगवती

उर्वशी की मंदिर को

अपना बता रही हैं, तब

से हम बहुत दुख में हैं।

हम बहुत पीड़ा में हैं। इस

बात का हम भारी विरोध

करते हैं।

तीर्थ पुरोहित ने जताई नाराजगी

ब्रदीनाथ के तीर्थ पुरोहित डॉक्टर ब्रजेश सर्ती ने भी नाराजगी जाहिर की है और उनका भी कहना है कि उर्वशी रौतेला के खिलाफ कार्यवाई हो। उन्होंने कहा, उर्वशी रौतेला द्वारा जो बयान दिया गया है वो बिल्कुल निदंशीय है। उत्तराखण्ड चारधाम तीर्थ महापंचायत उनके इस बयान को निदा करता है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उर्वशी रौतेला के खिलाफ कार्यवाई की जाए।

उर्वशी रौतेला का दावा

उन्होंने आगे ये भी कहा, हम ब्रदीनाथ और केदारनाथ मंदिर से भी मांग करते हैं कि उनको इस दिशा में एक्शन लेना चाहिए। उर्वशी ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत करते हुए ये बयान दिया था।

उन्होंने कहा था कि ब्रदीनाथ के पास जो उर्वशी मंदिर है वो उनके लिए समर्पित है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो चाहती है कि साथ में भी उनके नाम का मंदिर बने। हालांकि, आपको बता दें कि उत्तराखण्ड में जो मंदिर है वो उर्वशी रौतेला का नहीं बल्कि देवी उर्वशी का मंदिर है।

शाहरुख खान ने साल 2023 में एक-दो बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार बॉक्स टूटा था। पहले उन्होंने 'पठान' और फिर 'जवान' से सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद उसी साल 'डंकी' जैसी सुपरहिट फिल्म भी दी थी। शाहरुख की जवान उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीबूद्धि फिल्म बनी थी। वैसे ये कारनामा शाहरुख पहले भी कर चुके हैं। शाहरुख खान को 27 साल पहले आई एक फिल्म भी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर साबित हुई थी। उनकी मूरी ने अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे दिग्गजों की फिल्म को भी पछाड़ दिया था। शाहरुख की पिक्चर का बजट सिर्फ 10 करोड़ रुपये था, लेकिन इसने टिकट बिंदो पर 106 करोड़ रुपये को कलेक्शन करके कई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया थे।

'कुछ कुछ होता है' 1998 की सबसे कमाऊ फिल्म शाहरुख खान ने अपने 33 साल के करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों से फैसंस को अपना दीवाना बनाया है। उनकी बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में 'कुछ कुछ होता है' को भी शामिल किया जाता है। इसमें शाहरुख ने काजोल और रानी मुखर्जी जैसी मशहूर अदाकाराओं के साथ मिलकर बॉक्स ऑफिस पर धमात मचा दिया था।

'कुछ कुछ होता है' 1998 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई फिल्म 'दूल्हे राजा' थी जिसमें गोविंदा लीड रोल में थे। जबकि उस साल की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' थी, ये फिल्म हिट साबित हुई थी लेकिन शाहरुख की 'कुछ कुछ होता है' से आगे नहीं निकल पाई। इसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जोड़ी ने फैसंस का खबर मनोरंजन किया था। बड़े मियां छोटे मियां भी 10 करोड़ में ही बनी थी, लेकिन इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 35 करोड़ रुपये ही हो पाई थी।

5 भोजपुरी स्टार्स के बारे में वया सोचती हैं

# रानी चटर्जी

वन लाइन में एकट्रेस ने दिया जवाब

भोजपुरी सिनेमा आज के समय में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस इंडस्ट्री के कुछ सितारे देशभर में पहचाने जाते हैं और उनके गाने भी लोग खूब चाह के साथ सुनते हैं। भोजपुरी एकट्रेस रानी चटर्जी ने लगभग हर भोजपुरी स्टार्स के साथ काम किया है और जब उनके 5 स्टार्स के बारे में बन लाइन के अंदर चीजें पूँछी गई तो उन्होंने कॉन्फिंडेस के साथ इसका जवाब दिया था। 4.5 साल की एकट्रेस रानी चटर्जी ने मनोज कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म सुसुरा बड़ा पैसावाला (2003) से अपने एकट्रिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने लगभग सभी भोजपुरी स्टार्स के साथ काम किया और उनके लिए एकट्रेस ने क्या कहा, आइए।

रानी चटर्जी ने भोजपुरी स्टार्स के लिए क्या कहा?

का हाल बा पॉडकास्ट के एक एपिसोड में रानी चटर्जी पहुंची थीं जहां उन्होंने सभी सफालों के जवाब दिए। इस दौरान उनसे पूछा गया, 'भोजपुरी के 5 एक्टर जिनके नाम हैं उनके बारे में दो-दो बातें सभी के बारे में आपको बताना हैं। सभीसे पहले निरहुआ जी' इसपर रानी चटर्जी ने कहा, 'वो एक सज्जन आदमी हैं, जो हर किसी को जोड़कर रखना जानते हैं।' दूसरा नाम मनोज तिवारी का लिया गया तो रानी ने कहा था, 'मनोज जी, वो बदमाश हैं।'

रानी चटर्जी का जवाब किसी फिल्म के जिनमें बिना किसी बदलाव के लिए एक बात है?

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार्स कौन-कौन-

सिनेमा के सुपरस्टार्स कौन-कौन